

Cleaning of Riven in Tamil Nadu

3873. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have received a plan from the Government of Tamil Nadu for cleaning of rivers and environmental improvement of cities in Tamil Nadu:

(b) if so, the details thereof: and

(c) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No. Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Forest Land at Seelvasa of Dadra Nagar Haveli (UT.)

3874. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Seelvasa of Dadra Nagar Haveli UT. has more than 92.1 per cent of population belonging to scheduled tribes:

(b) whether it is a fact that the land of these tribals is covered under Forest Area: and

(c) whether it is also a fact that the land is the only source of income of tribal people in this area, and they are the sole owner of this land from their last forth father hereditary?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The Union Territory of Dadra Nagar Haveli. of which Seelvasa is the capital has, according to 1991 census, a population of 1,38,477 out of which 1,09,380 are Scheduled Tribes constituting 78.99% of the total population.

(b) and (c) 42.2% of the geographical area of the Union Territory is under forest cover. The tribals do not have exclusive ownership over the forest lands which are a State property. However, bulk of the population of the Union Territory including non tribals depend heavily on forests for timber and fuelwood and also as a source of earning wages through forestry activities for their livelihood, the tribals also enjoy exclusive rights for collection of Minor Forest produce free of cost as also other

privileges in the forest area like collection of fuelwood, leaves and grass etc. for their domestic consumption.

National Forest Policy

3875. SHRI RAM RATAN RAM : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether in the National Forest Policy, 1988, it was recommended that 33 per cent of the total geographical area of the country should be covered by forest:

(b) if so, what is the area under forest cover at present;

(c) whether present coverage is less than 33 per cent; and

(d) what are the reasons therefor and what steps Government propose to increase forest coverage in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) As per the State of Forest Report, 1991, the forest cover in the country' is 6,39,182 So., km.

(c) Yes, Sir.

(d) The main reasons for the less forest cover are biotic pressure and diversion of forest land for non-forestry purposes. To increase the forest cover, a massive afforestation programme. Social and Farm forestry under the 20-Point Programme is pursued vigorously with the people's participation. During Sixth and Seventh Five Year Plan, an area of 46.50 lakh hectares and 88.85 lakh hectares respectively, have been afforested.

जल-प्रदूषण

3876. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जल प्रदूषण पर काबू पाने में विफल रही है और इसी वजह से जल प्रदूषण को नहीं रोका जा सका है:

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नदि:खाव और उत्सर्जन की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को कार्यान्वित करने के संबंध में किए गए प्रयासों का राज्यवार ज्वारा क्या है: और

(ग) क्या यह सच है कि जल प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिःस्त्राव और उत्सर्जन की अधिकतम स्वीकार्य सीमा का उचित रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ?

पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) शहरी नदियों के साथ-साथ नदियों के कुछ भागों में जल प्रदूषण मुख्य रूप से इसलिए अधिक है, क्योंकि वहाँ पर अशोधित घरेलू मलजल तथा बहिःस्त्राव शोधन प्रणालियाँ न चलाने वाले कुछ उद्योगों से विसर्जन होता है। 16 ऐसी इकाइयों को बन्द करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। वे इकाइयाँ निम्नलिखित हैं :—

1. मेसर्स कश्मीर डिस्टिलरीज प्रा० लि०, बडमना, जम्मू
2. मेसर्स न्यू इंडिया डिस्टिलरीज, बसवपुर, साम्बा, जम्मू
3. मेसर्स ओ० आर० डिस्टिलरीज, गजुलामेहम, जिला चित्तूर
4. प्राइमा टैनरीज, ओबरी, बाराबंकी
5. टेक्नीकल एसोसिएट इंडस्ट्रीज लि०, बाराबंकी
6. मेसर्स आन्ध्र प्रदेश मेटलर्जिकल इंजीनियरी लि०

बेलाराम, जिला मेदक

7. मेसर्स वंडव को-ऑपरेटिव भुगर, पायाकरावपेट, डिजाल
8. मेसर्स एन० सी० आर० को-ऑपरेटिव भुगर लि०, जामपानी
9. मेसर्स पलेयर को-आप० भुगर लि०, खम्मम
10. मेसर्स बामसहारापेपर मिल्स लि०, मद्रपम (ग्राम व पो०), जिला श्रीकाकुलम
11. मेसर्स लेलंगाना पेपर मिल्स लि०, नई कंगुडम, जिला खम्मम
12. मेसर्स आदिवासी पेपर मिल्स लि०, बाम्परापेट, जिला खम्मम
13. मेसर्स निरकार्ज पेपर मिल्स लि०, गुडीपल्लुपुडी (सी०), जिला नेल्लोर
14. मेसर्स श्रीहनुमा फार्मा केमिकल (प्रा०) लि०, दोलेश्वरम, जिला ई०सी०

नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के तहत, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में नदियों के नीचे दिये गये उन भागों की शिनाख्त की गई है, जिनकी ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता

राज्य	नदी	प्रदूषित भाग
दिल्ली/उत्तर प्रदेश	यमुना	दिल्ली-इटावा दिल्ली, मथुरा और आगरा की शहरी सीमाएं
राजस्थान	चम्बल	नागदा के निचले भाग और कोटा के निचले भाग (15 कि०मी०)
उत्तर प्रदेश	काली	मोदी नगर के निचले भाग से गंगा के संगम तक
उत्तर प्रदेश	हिंदन	सहारनपुर से यमुना के संगम तक
मध्य प्रदेश	खान	इंदौर की शहरी सीमा, इंदौर के निचले भाग
मध्य प्रदेश	शिप्रा	उज्जैन की शहरी सीमाएं, उज्जैन का निचला भाग
बिहार/पश्चिम बंगाल	दामोदर	धनबाद के निचले भाग से हल्दिया तक
उत्तर प्रदेश	गोमती	लखनऊ से गंगा के संगम तक
कर्नाटक	कावेरी	तलाककावाड़ी से मैसूर जिले के पांच किमी० तक, यगाची सीमा
कर्नाटक		के० आर० सागर बांध से होगेनेकल तक
तमिलनाडु		उगानूर से ग्रैंड एनीकट तक
तमिलनाडु		ग्रैंड एनीकट से कुम्माकोनम तक
गुजरात	साबरमती	अहमदाबाद शहर के निकटवर्ती ऊपरी हिस्से से साबरमती आश्रम तक, साबरमती आश्रम से वावुया तक
पंजाब	सतलज	लुधियाना के निचले हिस्से से हरिके तक
बिहार	खगरीखा	हटिया बांध से भारागोरा तक
महाराष्ट्र	गोदावरी	नासिक के निचले हिस्से से नान्देड तक

महाराष्ट्र		नासिक और नान्देड की शहरी सीमाएं
आन्ध्र प्रदेश		माचेरियल और रामगुंडम से भद्रचलम तक
महाराष्ट्र	कृष्णा	कराड से सांगली तक
महाराष्ट्र		छेम नांध से नरसरोवड़ी तक
आन्ध्र प्रदेश		सहायक नदी नीरा
आन्ध्र प्रदेश		नागार्जुन सागर बांध तक और उस बांध से रिपेला के ऊपरी भाग तक
कर्नाटक	मद्रा	उदुगम स्थान से मद्रा बांध (कर्नाटक) के के० आई० ओ० सी० एल० के निचले हिस्से तक
उड़ीसा	ब्रह्मपणी	खंगुल निचला हिस्सा कामलंगा से भुवन तक
कर्नाटक	तुंगा	तीरथ हल्ली से मद्रा के संगम तक
मध्य प्रदेश	नर्मदा	जबलपुर शहर के साथ-साथ
मध्य प्रदेश	राप्ती	नेपा नगर के निचले हिस्से से बरहानपुर शहर तक
उड़ीसा	बेलवा	मंडीवीप और धिदिशा के साथ-साथ
हिमाचल प्रदेश	व्यास	मनाली से मंडी तक का ऊपरी हिस्सा
हिमाचल प्रदेश		मंडी के निचले हिस्से से हिमाचल प्रदेश सीमा तक
असम	कोलब्रोंग खलौंग	नागांव शहर के साथ-साथ (असम)
असम	भोगडोई	ओरहाट शहर (असम) के साथ-साथ
असम	बड़क	सिलचर शहर (असम) के साथ-साथ
मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल शहर (मणिपुर) के साथ-साथ
त्रिपुरा	हावड़ा	अगरतला शहर (त्रिपुरा) के साथ-साथ

(ग) जी. नहीं : विशिष्ट शिकायतें मिलने पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है।

प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिःस्त्रव, उत्सर्जन और परिवेशी और मानक निर्धारित किए गए हैं:
2. उद्योगों के स्थान-निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय शिक्षा-निर्देश तैयार किए गए हैं:
3. बहिःस्त्रवों और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित मानकों तक सीमित रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें:
4. केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से प्रदूषक उद्योगों के अनुपस्थानार्थ बहिःस्त्रव और उत्सर्जन मानकों संबंधी एक कार्य योजना तैयार की है:
5. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषक उद्योगों को प्रौढ़-माह वाले क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं:
6. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है:

7. छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के समूहों का सामूहिक बहिःस्त्रव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है:

8. लघु उद्योगों में प्रदूषण के निवारण के लिए नई औद्योगिकी खपताने पर सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है:

9. जल उपस्कर में वृद्धि की गई है ताकि जल संरक्षण और उसके पुनः प्रयोग को बढ़ावा मिल सके:

10. उद्योगों में पर्यावरणीय प्रबन्धन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदूषण निवारण के लिए उद्योगों को पुरस्कृत करने की एक योजना शुरू की गई है:

11. प्राकृतिक संसाधनों और कच्ची सामग्रियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय संपरीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है:

12. सड़क पर चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों के लिए मोटर-वाहन नियमावली, 1989 के तहत ओस उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं और ये 31 मार्च, 1990 से लागू हो गए हैं:

Pollution Control Board

3877. MISS SAROJ KHAPARDE : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :